

[2023] 6 एस. सी. आर. 203

/

कलकत्ता राज्य परिवहन निगम और ओआरएस. v.

आशित चक्रवर्ती और ओआरएस। (2023 की सिविल अपील संख्या 3462) 8 मई, 2023

/

[अभय एस. ओका और राजेश बिंदल, जे. जे.]

कलकत्ता राज्य परिवहन निगम कर्मचारी सेवा (मृत्यु सह सेवानिवृत्ति लाभ) विनियम, 1990-प्रत्यर्थी सं।1 निगम में 1981 में संचालक के विरचित में नियुक्त किया गया था जब कोई पेंशन योजना लागू नहीं थी, केवल अंशदायी भविष्य निधि (सी. पी. एफ.) योजना लागू थी-1990 के विनियम 1991 में कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना प्रदान करने के लिए बनाए गए थे, जो 01.04.1984 से प्रभावी थे-मौजूदा कर्मचारियों को 1990 के विनियमों के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का विकल्प देना था-प्रतिवादी संख्या।1 समय के भीतर अपना विकल्प प्रस्तुत किया-उन्होंने 2017 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग की-कुछ सेवानिवृत्ति लाभों के अलावा, उन्हें कोई पेंशन नहीं दी गई-प्रतिवादी नं।1, विचार नहीं किया गया-एकल न्यायाधीश द्वारा अनुज्ञात दायर रिट याचिका-खंड पीठ द्वारा बरकरार रखा गया आदेश-आयोजित:प्रत्यर्थी सं. द्वारा पेंशन प्राप्त करने के अधिकार की छूट के संबंध में अपीलार्थी द्वारा उठाए गए तर्क में कोई योग्यता नहीं है।1 - प्रतिवादी नं. द्वारा पेंशन प्राप्त करने के अधिकार का कोई सचेत परित्याग नहीं किया गया था।1 उसे उसकी पेंशन से वंचित करने के लिए-प्रतिवादी नं।1 वर्ष 1991 में 1990 के विनियमों के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया-इसके बाद, इसे लागू करना निगम का कर्तव्य था-केवल इसलिए कि उनके वेतन से कुछ गलत कटौती की गई थी और उन्हें सी. पी. एफ. योजना के सदस्य के रूप में माना गया था, उनके सही दावे को विफल करने का आधार नहीं हो सकता है-कर्मचारियों की संख्या के मामलों में 1990 के विनियमों को लागू करने में निगम की गलती थी, हालांकि इन्हें 04.01.1991 पर अधिसूचित किया गया था और 01.04.1984 से पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया था-निगम की ओर से किसी भी गलती के लिए, कर्मचारियों को पीड़ित नहीं किया जा सकता है-उच्च न्यायालय-सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 के दशक द्वारा पारित आदेशों में कोई त्रुटि नहीं।45.

/

/

/

/

/

कल्पराज धर्मशी और एक अन्य बनाम कोटक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स लिमिटेड और एक अन्य
(2021) 10 एससीसी 401 -

/

संदर्भित किया गया।

203 ए.

204 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 6 एस. सी. आर.

संदर्भित निर्णय

(2021) 10 एस. सी. सी. 401

संदर्भित

पैरा **10**

सिविल अपील की अधिकारिता 2023 की सिविल अपील संख्या 3462।

2019 के एफ. एम. ए. संख्या 692 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय के दिनांकित
05.03.2021 के निर्णय और आदेश से।

/

संजय आर हेगड़े, वरिष्ठ अधिवक्ता, अदील अहमद, राजा चटर्जी, पीयूष सचदेव, आदित्य पाठक,
मोहम्मद शारुक अली, राघव गुप्ता, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।

/

सुभाशीष भौमिक, मानस कुमार घोष, सुश्री सुष्मिता डे, सुश्री मनीषा पांडे, राहुल कुशवाहा, जॉन
थॉमस अरकल, सुश्री मणि माला रॉय, हर्ष गुप्ता, एच. के. नाइक, सुश्री तन्वी सिंह, भानु मिश्रा,
सुश्री आस्था शर्मा, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

/

राजेश बिंदल, जे।

अनुमति दी गई।

1. कलकत्ता में उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा 2019 के एफ. एम. ए. संख्या 692 में पारित दिनांक 1 के आदेश को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है, जिसमें 2018 की डब्ल्यू. पी. संख्या 6808 (डब्ल्यू) वाली रिट याचिका में एकल पीठ द्वारा पारित 2 के आदेश को बरकरार रखा गया था। 2. यह एक ऐसा मामला है जिसमें प्रतिवादी नं. 1 अपीलार्थी निगम के साथ संचालक के रूप में नियुक्त किया गया था। उस समय कोई पेंशन योजना लागू नहीं थी, केवल अंशदायी भविष्य निधि योजना लागू थी। 1991 में, सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 45 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निगम ने राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ, कलकत्ता राज्य परिवहन निगम कर्मचारी सेवा (मृत्यु सह सेवानिवृत्ति लाभ) विनियम, 1990 (संक्षेप में, "1990 विनियम") विरचित। उपरोक्त विनियम 1.4.1984 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ लागू हुए। 1990 के विनियमों ने अनिवार्य किया कि उक्त योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निगम के मौजूदा कर्मचारियों को 1990 के विनियमों के प्रकाशन की तारीख से छह महीने के भीतर लिखित विकल्प प्रस्तुत करना होगा, जिसमें वे सी. पी. एफ. धारक के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने के बजाय उक्त पेंशन योजना में जाने की इच्छा व्यक्त करेंगे। 1990 के विनियमों में यह भी प्रावधान किया गया था कि यह मौजूदा ए के लिए वैकल्पिक होगा।

/

/

/

/

205

कलकत्ता राज्य परिवहन निगम बनाम आशीष चक्रवर्ती [राजेश बिंदल, जे.] ए.

तथापि, कर्मचारीगण, यह 1990 के विनियमों की अधिसूचना की तारीख को और उसके बाद नए प्रवेशकों के लिए बाध्यकारी होगा।

3. प्रत्यर्थी नं. 1 उन्होंने पेंशन योजना का विकल्प चुना। 21.7.2017 पर, उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुना, जिसे निगम द्वारा स्वीकार कर लिया गया और वे 31.7.2017 पर सेवानिवृत्त हुए। अपनी सेवानिवृत्ति पर प्रत्यर्थी नं. 1 को सी. पी. एफ. योगदान के लिए '13,28,495,' 7,44,265-ग्रेज्युटी के लिए, '2,58,012-वी. आर. एस. मुआवजे के लिए और छुट्टी वेतन के लिए' 2,409/- की राशि का भुगतान किया गया था। चूंकि प्रतिवादी को कोई पेंशन नहीं दी गई थी। 1, उन्होंने 8.5.2018 पर एक अभ्यावेदन दिया। चूंकि उनके दावे पर विचार नहीं किया गया था, इसलिए उन्होंने रिट याचिका दायर की, जिसे एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 17.8.2018 के आदेश द्वारा अनुज्ञात गई थी। आदेश का कार्यात्मक भाग इस प्रकार है:

/

/

“मैं याचिकाकर्ता को भविष्य निधि के नियोक्ता के हिस्से के साथ-साथ पेंशन योग्य राशि से अधिक भुगतान की गई ग्रेच्युटी की राशि निगम को दो सप्ताह की अवधि के भीतर 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ वापस करने का निर्देश देता हूँ। इस तरह के भुगतान की प्राप्ति पर, प्रतिवादी अगस्त 2018 के महीने के लिए दो सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता के पक्ष में पेंशन जारी करेंगे और निगम के साथ सामान्य प्रथा के अनुसार मासिक पेंशन का भुगतान करते रहेंगे।

/

जहां तक बकाया पेंशन का संबंध है, यानी अगस्त, 2018 से जुलाई, 2018 तक, उत्तरदाताओं को इसे तीन समान मासिक किश्तों में समाप्त करने का निर्देश दिया जाता है, जिनमें से पहली किश्त का भुगतान 15 सितंबर, 2018 तक किया जाएगा। पेंशन के बकाया पर प्रति वर्ष 6 प्रतिशत की दर से ब्याज लगेगा जिसे तीन किश्तों में समान रूप से वितरित किया जाएगा। यदि पेंशन राशि याचिकाकर्ता के बैंक खाते में भेजी जाती है, तो प्रतिवादी अधिकारी याचिकाकर्ता को प्रत्येक मासिक किश्त के लिए विभाजन गणना की एक प्रति देंगे। ”

/

/

निगम ने इस आदेश को अपील में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने एकल पीठ द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा।

/

4. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रत्यर्थी नहीं। 1991 में 1990 के विनियमों के संदर्भ में पेंशन योजना के लिए अपना विकल्प प्रस्तुत किया। हालाँकि, इसके बाद बार-बार प्रतिवादी सं। 1 यह दर्शाता है कि वास्तव में उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनके वेतन से भविष्य निधि के लिए नियमित कटौती की जाती थी। उन्हें बयान भेजे जा रहे थे। हालांकि, उन्होंने कभी विरोध नहीं किया

/

206

/

[2023] 6 एस सी आर।

यह। उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति के बाद ही इस मुद्दे को उठाया। ऐसी परिस्थितियों में उसे पेंशन योजना का लाभ उठाने की अनुज्ञात नहीं दी जानी चाहिए। 5. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील नं. 1 ने प्रस्तुत किया कि 1990 के विनियमों के अंतर्गत आवश्यकता निर्धारित समय के भीतर एक विकल्प प्रस्तुत करने की थी। प्रत्यर्थी नं. 1 पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए अपना विकल्प प्रस्तुत किया था। इसके बाद, यह नियोक्ता, अर्थात् अपीलार्थी का कर्तव्य था कि वह अपने वेतन और विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत उससे की जाने वाली कटौती की ठीक से गणना करे। यदि निगम द्वारा कोई त्रुटि की गई थी, तो उसे उस कारण से पीड़ित नहीं किया जाना चाहिए। प्रत्यर्थी को जो भी राशि का भुगतान किया गया था। 1 अपनी सेवानिवृत्ति पर, उन्होंने यह मानते हुए इसे स्वीकार कर लिया कि यह उनकी सेवानिवृत्ति पर देय हो सकता है। उन्हें नहीं पता था कि निगम उन्हें पेंशन नहीं देगा और कुछ अन्य राशि का अतिरिक्त भुगतान किया गया है। यह केवल निगम की गलती थी। यह केवल प्रतिवादी सं. की सेवानिवृत्ति के बाद है। 1 कि उन्हें पता चला कि उन्हें पेंशन नहीं दी जा रही है। चूंकि उनके द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया गया था, इसलिए उन्हें उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश और खंड पीठ द्वारा पारित आदेशों में कोई त्रुटि नहीं है। समानताओं को संतुलित किया गया है। राशि, जो प्रत्यर्थी सं. के कारण नहीं थी। 1, अपीलार्थी निगम को ब्याज के साथ वापस करने का निर्देश दिया गया है और पेंशन की बकाया राशि जारी करने पर उसे वही ब्याज दिया जाना आवश्यक है। वास्तव में, जब प्रत्यर्थी नहीं। 1 उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और रिट याचिका को अनुज्ञात गई, यह उनकी सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद थी। हालांकि, निगम ने टालने योग्य मुकदमेबाजी में लगभग पांच साल का समय बर्बाद किया है और प्रतिवादी नं. 1 अपने सही दावे के बारे में।

/

/

/

/

6. पक्षों की ओर से विद्वानों की सलाह सुनी और पेपर का अध्ययन किया

/

किताब।

7. निर्विवाद तथ्य यह है कि प्रतिवादी नं. 1 निगम में 6.7.1981 पर संचालक के रूप में नियुक्त किया गया था। 1990 के विनियमों को कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना प्रदान करने के लिए विरचित किया गया था, जो 1.4.1984 से प्रभावी था। इसके संदर्भ में, मौजूदा कर्मचारियों को 1990 के विनियमों के अंतर्गत लाभ उठाने का विकल्प देना था। इससे पहले अंशदायी पेंशन योजना लागू थी। यह विवाद में नहीं है कि प्रत्यर्थी नं. 1 समय के भीतर अपना विकल्प प्रस्तुत कर दिया था। उन्होंने 21.7.2017, W. E. F. 31.07.2017 पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की

मांग की।उन्हें कुछ सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान किया गया था, हालांकि, उन्हें कोई पेंशन नहीं दी गई थी जिसके लिए उन्होंने विकल्प का उपयोग किया था।उन्होंने एक अभ्यावेदन ए दायर किया

/

/

207

कलकत्ता राज्य परिवहन निगम बनाम आशीष चक्रवर्ती [राजेश बिंदल, जे.] ए.

8.5.2018 पर।उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।इसलिए उन्होंने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की।

8. प्रारंभ में एकल न्यायाधीश के समक्ष लिया गया रुख यह था कि प्रत्यर्थी नं।1 निर्धारित समय के भीतर अपना विकल्प प्रस्तुत नहीं किया था।हालांकि, न्यायालय के समक्ष पेश किए गए विभिन्न दस्तावेजों के अवलोकन पर, यह पाया गया कि प्रतिवादी नं।1 1990 के विनियमों को अधिसूचित किए जाने के तुरंत बाद वर्ष 1991 में उन्होंने अपना विकल्प प्रस्तुत किया था। प्रत्यर्थी का दावा सं।1 इस आधार पर पराजित होने की मांग की गई कि विकल्प का प्रयोग करने के बाद भी, सी. पी. एफ. योजना में सदस्यता के संदर्भ में उनके वेतन से योगदान काटा जा रहा था, जिस पर उन्होंने कभी आपत्ति नहीं जताई।इसके अलावा, याचिका दायर करने की मांग की गई थी कि बड़ी संख्या में समान रूप से स्थित कर्मचारी हैं जो यह दावा करेंगे।

/

/

9. हालाँकि, उपरोक्त दलीलें योग्य नहीं पाई गईं, इसलिए उच्च न्यायालय ने उन्हें खारिज कर दिया।यह पाया गया कि प्रत्यर्थी सं. द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प पर कार्रवाई नहीं करने में निगम की गलती थी।1. अंत में, प्रतिवादी नं. को निर्देश दिया गया।1 भविष्य निधि के नियोक्ता के हिस्से के साथ-साथ निगम को प्रति वर्ष 6 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ अधिक भुगतान की गई उपदान राशि को दो सप्ताह के भीतर वापस करना।राशि प्राप्त होने पर निगम को अगस्त 2018 से दो सप्ताह के भीतर पेंशन जारी करने का निर्देश दिया गया था।जहां तक अगस्त 2017 से जुलाई 2018 तक पेंशन के बकाया का संबंध है, 15 सितंबर, 2018 से इसे तीन समान मासिक किश्तों में समाप्त करने का निर्देश दिया गया था।बकाया पर सालाना 6 प्रतिशत की दर से ब्याज भी देना था।यह राशि प्रत्यर्थी सं. के बैंक खाते में हस्तांतरित की जानी थी।1. विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित कानूनी रूप से पोषणीय और न्यायसंगत आदेश के बावजूद, निगम ने अदालत के भीतर अपील दायर की।दिनांक 25.6.2019 के आदेश के माध्यम से, डिवीजन बेंच ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के संचालन पर रोक

लगा दी।प्रत्यर्थी द्वारा दायर आवेदन पर विचार करने पर सं.1 अंतरिम रोक को हटाने के लिए, अपील पर ही सुनवाई की गई और अंत में आक्षेपित निर्णय के माध्यम से निर्णय लिया गया। डिवीजन बेंच के समक्ष एकमात्र तर्क छूट के बारे में था।लेकिन, इसे स्वीकार नहीं किया गया।इस सिद्धांत को उस स्थिति में लागू किया जा सकता है जब मौजूदा कानूनी अधिकार को जानबूझकर त्याग दिया गया हो।

/

/

/

/

10. हम अपीलार्थी के वकील द्वारा उठाए गए उसी तर्क में कोई योग्यता नहीं पाते हैं जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था, अर्थात् प्रतिवादी सं.1. वहाँ

/

208

/

[2023] 6 एस सी आर।

प्रतिवादी सं. द्वारा पेंशन प्राप्त करने के अधिकार का जानबूझकर त्याग नहीं किया गया था।1 उसे उसकी पेंशन से वंचित करना।संदर्भ दिया जा सकता है।

कल्पराज धर्मशी और एक अन्य बनाम कोटक निवेश सलाहकार लिमिटेड और एक अन्य मामले में इस न्यायालय के निर्णय के लिए।उसका प्रासंगिक पैरा 119

इसे नीचे निकाला गया है:- “119. इस बात पर विचार करने के लिए कि किसी पक्ष ने अपने अधिकारों को माफ किया है या नहीं, किसी पक्ष के आचरण पर विचार करना प्रासंगिक होगा।छूट स्थापित करने के लिए, यह स्थापित करना होगा कि एक पक्ष ने स्पष्ट रूप से या अपने आचरण से इस तरह से काम किया है, जो उसके अधिकारों की निरंतरता के साथ असंगत है।हालाँकि, केवल भोग के कार्य छूट के बराबर नहीं होंगे।छूट का दावा करने वाला पक्ष भी छूट के लाभ का दावा करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि उसने उसी पर भरोसा करते हुए अपनी स्थिति में बदलाव नहीं किया हो। ”

/

/

11. यह विवाद में नहीं है कि प्रत्यर्थी नं।1 वर्ष 1991 में 1990 के विनियमों के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया था। इसके बाद, निगम का कर्तव्य था कि वह इसे लागू करे। केवल इसलिए कि उनके वेतन से कुछ गलत कटौती की गई थी और उन्हें सी. पी. एफ. योजना का सदस्य माना गया था, उनके सही दावे को विफल करने के लिए एक आधार के रूप में उठाए जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। पेंशन प्रत्यर्थी की सेवानिवृत्ति के बाद शुरू होनी थी। जब उसे उन्हें जारी नहीं किया गया, तो तुरंत उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया। चूंकि अपीलार्थी से कोई जवाब नहीं मिला था, इसलिए रिट याचिका दायर की गई थी। यह तर्क कि समान रूप से स्थित कई कर्मचारी हैं जो अपने दावे भी पेश करेंगे, इस न्यायालय को प्रतिवादी को राहत देने से नहीं रोकेगा, जो वैध रूप से उसके कारण है। बल्कि इस तर्क से पता चलता है कि कर्मचारियों की संख्या के मामलों में 1990 के विनियमों को लागू करने में निगम की गलती थी, हालांकि उन्हें 4.1.1991 पर अधिसूचित किया गया था और 1.4.1984 से पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया था। तकनीकी आपत्तियाँ उठाने की मांग की जाती है, जो मान्य नहीं हैं। निगम की ओर से किसी भी गलती के लिए कर्मचारियों को पीड़ित नहीं किया जा सकता है।

/

/

/

12. हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं। तदनुसार अपील खारिज कर दी जाती है।

/

दिव्या पांडे

याचिका खारिज कर दी गई।

(सहायक: रूपांशी विरंग, एलसीआरए)

1 (2021) 10 एस. सी. सी. 401

/